अवध की आवाज

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

www.avadhkaawaz.com

वर्ष–10 अंक–229 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ गुरुवार 18 नवम्बर 2021 पृष्ठ – 8 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

अमन चैन के लिए 2022 के विस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर रहेगाः अखिलेश

गाजीपुर (उप्र (वेब वार्ता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अमन चौन के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का दावा करते हुए बुधवार को कहा कि आगामी चुनाव में पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश ने एक बार फिर कहा कि एक्सप्रेस–वे सपा सरकार की देन है, लेकिन मौजूदा सरकार में एक्सप्रेस–वे का विकास आधा अधूरा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सपा सरकार ने मंडी सहित तमाम सरकारी सुविधाओं का ढांचा तैयार किया था, जिसे पूरा नहीं किया जा सका है। उन्होंने गाजीपुर में अपने सम्बोधन में कहा कि आने वाले समय में जो बदलाव की लहर दिख रही है और गाजीपुर सीमा से लेकर पूरे प्रदेश में भाजपा का सफाया होगा। राज्य में अमन चौन के लिए अगले साल होने वाले चुनाव में बदलाव होकर रहेगा। गौरतलब हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का उद्घाटन किया था। इस एक्सप्रेस–वे के बारे में सपा प्रमुख का दावा है कि इसका काम उनकी सरकार में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस–वे अभी आधा अधूरा है, पूरी तरह तैयार नही हुआ है। इस एक्सप्रेस–वे को बनाने का सपना अगर किसी ने देखा था तो वह समाजवादियों ने देखा था, ताकि यहां से दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी कम हो जाये और यह एक्सप्रेस–वे खुशहाली का एक्सप्रेस वे हो। इस एक्सप्रेस–वे के किनारे किसानों के लिए मंडी बनना है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार में जो जो हो रहा है, वह किसी से छिपा नही हैं। डीजल–पेट्रोल मंहगा हो गया, ये वही लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पलज में चलने वाले किसान को भी हवाई जहाज में बिठाएंगे। जिस तरह से डीजल–पेट्रोल मंहगा है, गरीब किसान की गाड़ी नही चल पा रही, खाद की चोरी हो रही है।

अगले 25 साल देश के विधायी सदनों में गूंजें केवल 'कर्त्तव्य' का मंत्र : मोदी

शिमला (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद एवं देश के पीठासीन अधिकारियों का आज आह्वान किया कि आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल तक सदनों में बार बार 'कर्तव्य' के मंत्र पर जोर दें तथा विधायी निकायों के सदनों में गुणवत्तापूर्ण परिचर्चा के लिए अलग से समय निर्धारित करें जिसमें मर्यादा, गंभीरता एवं अनुशासन हो तथा इससे स्वस्थ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हो। मोदी ने आज यहां संसद एवं विधानमंडलों के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी सम्मेलन का नई दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 82वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन 16, 17 एवं 18 नवंबर को यहां हो रहा है। देश के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत 1921 में हुई थी और पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। इसलिये शताब्दी सम्मेलन का आयोजन भी शिमला में किया जा रहा है। सम्मेलन में श्री बिरला के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी संबोधित किया। सम्मेलन मेंदेश के सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। श्री मोदी ने अपने संबोधन में सदन में नई कार्यप्रणाली को लेकर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा, "हमारे सदन की परम्पराएँ और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हों, हमारी नीतियाँ, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को मजबूत करने वाले हों, सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार–व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के समक्ष विचारणीय प्रश्न रखते हुए कहा, "क्या साल में 3–4 दिन सदन में ऐसे रखे जा सकते हैं जिसमें समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे जनप्रतिनिधि अपना अनुभव बताएं, अपने समाज जीवन के इस पक्ष के बारे में भी देश को बताएं। आप देखिएगा, इससे दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी

कितना कुछ सीखने को मिलेगा।" उन्होंने कहा कि इससे रचनात्मक समाज के लोगों को भी राजनीतिज्ञों के प्रति नकारात्मक भाव को कम करके उनसे जुड़ने और स्वयं राजनीति से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार से राजनीति में बहुत परिवर्तन आएगा। उन्होंने विधायी निकायों में परिचर्चा को स्वस्थ बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों को सुझाव देते प्रश्न किया, "हम गुणवत्तापूर्ण परिचर्चा के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? ऐसी परिचर्चा जिसमें मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, वह रोजमर्रा की राजनीति से मुक्त हो और कोई किसी पर राजनीतिक छींटाकशी ना करे। एक तरह से वो सदन का सबसे स्वस्थ समय हो, स्वस्थ दिवस हो।" उन्होंने कहा कि सदन में ज्यादातर सदस्य पहली बार चुन कर आये होते हैं और उनमें जनता के मुद्दों को लेकर बहुत ऊर्जा होती है। सदन में ताजगी लाने और नई कार्यप्रणाली विकसित करने की जरूरत है। नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए। सदन की गरिमा और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने ही होंगे। इसमे सभी पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने सदन की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए नियमों में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा। इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा और परिचर्चा बहुत जरूरी है। सदन में युवा सदस्यों को, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने तकनीक को भी प्रमुख स्थान दिये जाने पर बल देते हुए कहा, "वन नेशन–वन राशन कार्ड की तर्ज पर मेरा एक विचार 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म' का है। एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बल दे, बल्कि देश की सभी लोकतान्त्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे।" मोदी ने आजादी के अमृतकाल से लेकर आजादी के शताब्दी वर्ष के बीच 25 वर्ष के दौरान देश में कर्त्तव्य को सर्वाधिक महत्व दिये जाने का आह्वान करते हुए कहा, "अगले 25 वर्ष, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम एक ही मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या – कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य।" उन्होंने कहा कि हर बात में कर्त्तव्य सर्वोपरि है। 50 साल की कार्यशैली में कर्त्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सदनों में ये संदेश बार बार दोहराया जायेगा तो देश के नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह 130 करोड़ भारतीयों को कर्त्तव्य का बोध कराके देश को कई गुना बढ़ाने का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए लोकतन्त्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतन्त्र तो भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रकृति है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वर्षों में, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प 'सबके प्रयास' से ही पूरे होंगे। और लोकतन्त्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम 'सबका प्रयास' की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। उन्होंने कहा कि चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी–लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का भी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी, एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा, हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है। तीन दिन के इस सम्मेलन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशेष शिविर में 45 लोगों ने कराई रजिस्ट्री

दो दिवसीय शिविर के पहले दिन 115 लोगों ने किया सम्पर्क, 9 लोगों को मौके पर ही जारी किये गये आवंटन पत्र

अवध की आवाज

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी द्वारा आवंटियों की सुविधा के लिए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर निबन्ध

आयोजन किया गया। इस शिविर को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप कैम्प में भारी भीड़ उमड़ी। प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में अधिकारियों ने सभी प्रकरणों की त्वरित सुनवाई करते हुए उनका निस्तारण किया। रजिस्ट्री शिविर के विशय में प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि एक ही पटल पर आवंटियों के पक्ष में निबन्धन कराने के उद्देष्य से आयोजित षिविर में आज कुल 115 लोगों ने सम्पर्क किया गया। इसके साथ ही 45 आवंटियों को आज रजिस्ट्री हेतु निबन्धन प्रपत्र भी उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु आयोजित षिविर में आज 9 लोगों को मौके पर ही पवन कुमार गंगवार, सचिव प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन पत्र निर्गत किये गयें। यह विषेश षिविर कल दिनांक–18 नवम्बर को भी जारी रहेगा।

ग्रीन कॉरीडोर के साइड स्लोप्स पर लगेंगे सोलर पैनल

लखनऊ ग्रीन कॉरीडोर के साइड स्लोप्स पर सोलर पैनल लगाये जाएंगे, जिससे कि कई मेगा वॉट प्रदूशण मुक्त ऊर्जा का उत्पादन होगा। इससे न सिर्फ ग्रीन कॉरीडोर में लगाये जाने वाले पोल लाइटों को बिजली की आपूर्ति होगी बल्कि षेश बिजली से षहर की कई अन्य इमारतें भी रोषन होंगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्षध्मण्डलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को प्राधिकरण भवन में हुई लखनऊ ग्रीन कॉरीडोर की बैठक में इसका प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा परियोजना के लिए लैंड बैंक बनाने हेतु समस्त विभागों से उनके पास उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण मांगा गया। इस दौरान कई विभागों द्वारा आंकड़ों सहित भूमि का विवरण उपलब्ध कराया गया, जिसकी अध्यक्ष द्वारा समीक्षा

कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये। वहीं अन्य विभागों को दो दिन के अन्दर लैंड बैंक का डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, वन विभाग, आबकारी विभाग, षिक्षा विभाग, कष्शि विभाग, परिवहन और समाज कल्याण सहित समस्त विभागों के मण्डलीय स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट के सदस्य ए0के0 सेंगर ने ग्रीन कॉरीडोर का प्रेजेन्टेषन दिया, जिसमें सभी सदस्यों से सुझाव भी मांगे गये।

एयिर का भुगतान न होने पर होमगार्डो को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना

अवध की आवाज

कानपुर। होमगार्डों को एयिर ना मिलने पर होमगार्डों में काफी आक्रोश है आपको बता दें होमगार्ड योगेश्वर निगम ने बताया कि नगर निगम में तैनात होमगार्डो का अभी तक एयिर का भुगतान नहीं हुआ। जिसको 2 माह पूर्व से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। होमगार्ड योगेश्वर निगम ने बताया कि हमारे घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण पूरे परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा यह भुगतान होना है जिसको नगर आयुक्त होमगार्डो का भुगतान नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एयिर का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया था जिसको कानपुर नगर के आलाअधिकारी आदेश का नहीं करते हैं पालन। होमगार्ड योगेश्वर निगम ने बताया कि बीते माह पूर्व में एक्सीडेंट भी हो गया था। जिसमें उनको काफी गंभीर चोटें भी आई थी जिसका लंबा इलाज चल रहा है। घर की आर्थिक तंगी ठीक नहीं है। जिसे लेकर होमगार्ड योगेश्वर निगम ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। होमगार्ड का परिवार इलाज कराने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि अगर मेरा एयिर का भुगतान नहीं कराया गया तो प्रार्थी व उसका पूरा परिवार अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर होगा।

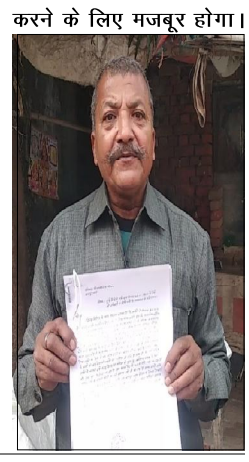

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने गुमशुदा बालिकाओं/महिलाओं की शीघ्र बरामदगी के संबंध में उनके परिजनों व विवेचकों के साथ की गोष्ठी,दिए आवश्यक दिशा निर्देश, वादी/परिजनों को दिलाया शीघ्र बरामदगी का भरोसा

अवध की आवाज ब्यूरो

गोंडा। बुधवार को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस कार्यालय सभागार में ऐसे गुमशुदा बालिकाओं/महिलाओं जिनकी अब तक बरामदगी नही हो सकी है, के संबंध में पंजीकृत मुकदमों के बारे में गुमशुदा बालिकाओं/महिलाओं के परिजनो व संबंधित विवेचको के साथ गोष्ठी कर बरामदगी के संबंध में वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। जिसमें पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक गुमशुदा बालिकाओं/महिलाओं के सम्बन्ध में उनके परिजनों व विवेचको से वार्ता की तथा परिजनों द्वारा दिये गये संकेत के आधार पर विवेचको को अग्रिम कार्यवाही करते हुए बरामदगी के निर्देश दिये। साथ ही सभी वादियों को उनके बालिकाओं/महिलाओं की शीघ्र बरामदगी करने का भरोसा भी दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि विवेचकगण प्रत्येक मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए गुमशुदा बालिकाओं/महिलाओं की शीघ्र बरामदगी करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस टीम को भी विवेचको के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए प्राप्त गोपनीय सूचनाओं/सूत्रों के अनुसार लगातार मॉनिटरिंग करते बालकों/महिलाओं की शीघ्र बरामदगी के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी सदर लक्ष्मीकांत गौतम, सर्विलांस प्रभारी संतोष कुमार सिंह तथा संबंधित विवेचकगण व मुकदमों के वादी/परिजन उपस्थित रहे।

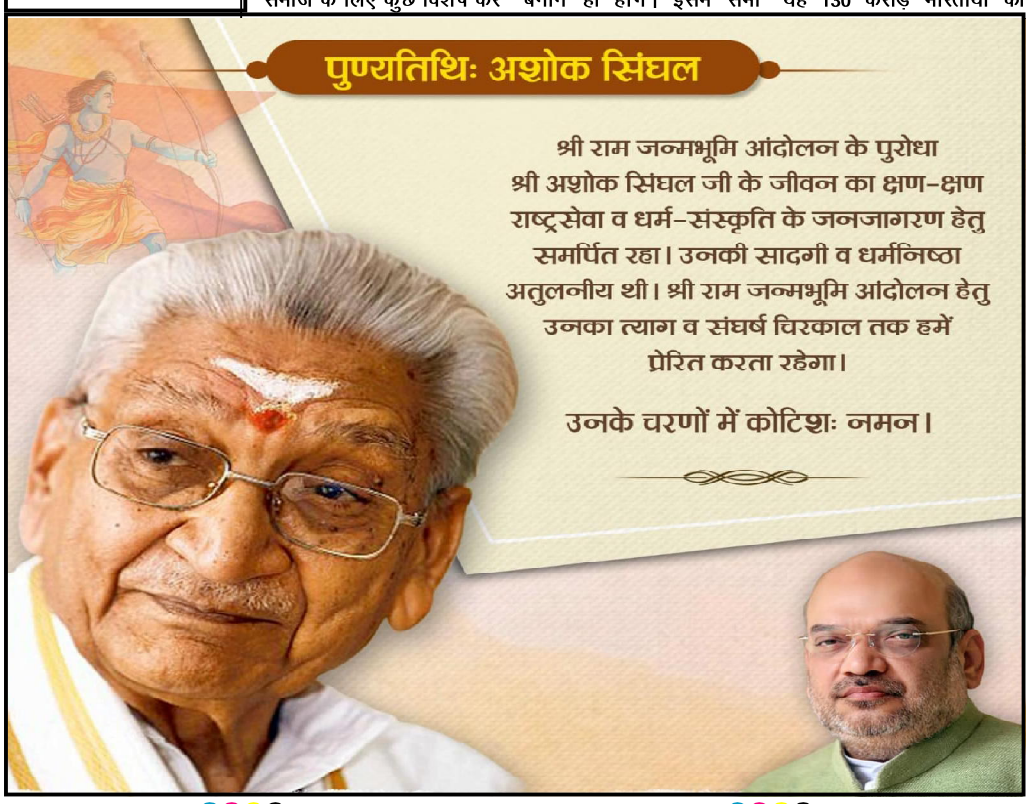

सम्पादकीय

जनजातीय समाज में आत्म-निर्भरता का आत्म-विश्वास

आजादी के अमश्त महोत्सव वर्ष में 15 नवम्बर 2021 को प्रध ाानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भोपाल में मध्यप्रदेश के जनजातीय समाज के लिए अनेक नयी और अनूठी योजनाओं की बौछार हुई।

इन योजनाओं की सौगात और महासम्मेलन में मिले मान–सम्मान से पूरे जनजातीय समाज में आत्म–निर्भरता का आत्म–विश्वास जागा है। साथ ही वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं।

संभवतः यह पहला अवसर था, जब प्रदेश ही नहीं देश में पहली बार लाखों की तादाद में जनजातीय वर्ग के लोग एक साथ राजधानी भोपाल में एकत्र हुए और भरपूर सम्मान भी पाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जनजातीय भाई–बहनों के लिए अभिभावक की भूमिका निभाते हुए उनके आने–जाने, रहने और खाने–पीने की समुचित व्यवस्थाएँ भी की। जनजातीय गौरव दिवस के अगले दिन करीब 700 जनजातीय कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर स्वल्पाहार कर उन्हें आनंदित कर दिया।

जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के एक्शन प्लान पर अमल शुरू प्रदेश में लगभग डेढ़ करोड़ आबादी वाले जनजातीय वर्ग को समाज की मुख्य–धारा से जोड़ने विकास का जो समग्र एक्शन प्लान बना, उसे अमल में लाने में कोई देरी नहीं की गई। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ष्राशन आपके ग्रामष योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक 24 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री चौहान ने योजना में लगने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जनजातीय विकासखण्डों के लिए रवाना कर योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत कर दी। अब इस वर्ग को राशन लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उनके समय की भी बचत होगी।

जनजातीय गौरव दिवस पर प्रध ाानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश राज्य सिकेल सेल मिशन का भी शुभारंभ किया। मिशन की गतिविधियां भी तत्काल प्रारंभ कर दी गई है। प्रधानमंत्री के हाथों एक महिला हितग्राही को मिशन अंतर्गत जांच रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया गया। इससे जनजातीय वर्ग को सिकल सेल जैसे अनुवांशिक रोग से निजात मिलेगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा।

जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा को अमल में लाते हुए ही अगले दिन संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस. आर/सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वश्क्षारोपण की नीति अनुमोदित कर दी गई। यहां यह बात साबित होती है कि मुख्यमंत्री चौहान ने जनजातीय समाज के उद्धार के लिए जो कदम बढ़ाए, उन्हें पूरा करने में वे कतई देरी नहीं होने दे रहे हैं। अब यह भी निर्णय लिया गया है कि पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेंदूपत्ता बेचने का कार्य ग्राम वन समिति/ग्राम सभा को दिया जायेगा। वनोपज से बाँस–बल्ली और जलाऊ लकड़ी पर वन समिति का ही अधिकार होगा। समिति उसको बेचकर आय कमा सकेगी। कटाई से जो इमारती लकड़ी प्राप्त होगी उसका भी एक अंश समिति को जाएगा। इसी तरह देवारण्य योजना में वनोत्पाद और वन औषधि को बढ़ावा देने के साथ वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय वर्ग को सबल बनाने के लिए जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एकलव्य मॉडल रेसीडेंसियल स्कूलों की सौगात भी प्रदेश को दी। मुख्यमंत्री चौहान ने जनजातीय वर्ग के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ जनजाति के बेटे–बेटियों को नीट और जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी कराने की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेज के साथ नीट और जेईई में चयन हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा उनकी पूरी फीस भरने का फैसला भी लिया है।

जनजातीय समाज के युवाओं को रोजगार और स्व–रोजगार उपलब्ध ा कराने के लिए भी अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ जनजातीय वर्ग के शिक्षित युवाओं को भी मिलेगा। मंत्रि–परिषद ने आज ही इस योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी फैसला किया है कि प्रत्येक जनजाति बहुल गाँव में 4 युवाओं को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। जनजातीय भाई–बहनों को पुलिस एवं सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। आगामी एक वर्ष में शासकीय विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही स्व–रोजगार के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए एकीकृत योजना बनाई जाएगी। प्रदेश के ऐसे अंचलों, जहाँ जनजातीय महा नायकों की कर्म स्थली रही है, में बड़े शासकीय संस्थानों का नाम जनजातीय महानायकों के नाम पर रखकर उनके गौरव को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रध ाानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करते हुए स्टेशन के आधुनिकीकरण का लोकार्पण भी किया। राज्य सरकार हाल ही में छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर चुकी है।

मंगलवार को हुई राज्य मंत्रि–परिषद की बैठक में इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज को जबलपुर में राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के स्मारक एवं संग्रहालय, के निर्माण कार्य के लिये राज्य शासन के प्रचलित शिड्यूल ऑफ रेट एवं उस पर 9 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क पर टर्न की बेसिस पर निविदा पद्धति की निर्धारित प्रक्रिया से छूट दी गई है। साथ ही कार्यादेश देने एवं उक्त कार्य में भविष्य में विस्तार आदि एवं संग्रहालय संचालन का कार्य स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के बाद एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आई.एन.टी.ए.सी.एच से ही कराए जाने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन नये कदम और पूर्व में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतश्त्व में उनके हित में किये गये कार्यों से मध्यप्रदेश का जनजातीय समाज आत्म–गौरव और आत्म–विश्वास के साथ आत्म–निर्भरता के पथ पर अग्रसर हो सकेगा।

एक्सप्रेस वे के औद्योगिक गलियारे

–डॉ. दिलीप अग्निहोत्री–

विगत साढ़े चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ढांचागत व अन्य निर्माण के रिकार्ड कायम हुए हैं। इसमें एक्सप्रेस वे और कनेक्टिविटी भी शामिल है। औद्योगिक विकास के लिए इन सुविधाओं का विस्तार अपरिहार्य होता है।

इसके साथ ही बिजली की उपलब्ध ाता, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सिंगल विंडो की पारदर्शी व्यवस्था, भूमि बैंक की स्थापना आदि भी आवश्यक होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेस वे को औद्योगिक विकास और प्रगति से जोड़ दिया है। उन्होंने एक्सप्रेस वे निर्माण मात्र को ही पर्याप्त नहीं माना। इनकी वास्तविक उपयोगिता औद्योगिक विकास से ही हो सकती है। वर्तमान सरकार इसी मान्यता के आधार पर एक्सप्रेस वे का निर्माण करा रही है।

योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेस वे को उद्योग से जोड़कर चल रहे हैं। इससे इनके निकट के गांव, कस्बे और नगर सभी को लाभ होगा। योगी की योजना में एक्सप्रेस वे केवल प्रमुख महानगरों को जोड़ने की कवायद नहीं है। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी बढ़ाने में सहायक होंगे। इसके दृष्टिगत निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के समानांतर लैंड बैंक भी स्थापित हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपो व इन्वेस्टर्स समिट में निवेश के समय से ही यह योजना आगे बढ़ रही है। इसके अलावा प्रत्येक पचास किमी पर यात्री सुविधा के लिए ढांचागत निर्माण किया जाएगा। एकबार फिर योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक विकास एवं व्यावसायिक उपयोग के रूप में पहले से ही चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दुर्घटनाओं की न्यूनतम आशंका के लिए भी प्रारंभ से ही उपाय किए जाएंगे। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए एक इंच भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। यह कार्य वर्तमान सरकार किया। यह पूर्व निर्धारित लागत से कम पर बन रहा है। पहले इसकी लागत ज्यादा आ रही थी। इसके अलावा जिला व तहसील संपर्क मार्गों को फोर लेन बनाने, हवाई यात्रा सुविधा बढ़ाने का उल्लेखनीय कार्य हुआ है। पहले दो हवाई अड्डे प्रयोग में थे। इनकी संख्या नौ हो गई है। ग्यारह हवाई अड्डों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जेवर में स्थापित किये जा रहे नोएडा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना विश्व की सौ सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण भी चल रहा है। पांच एक्सप्रेस वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई प्रदान करेंगे। सभी जनपदों में बिना भेदभाव के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में कई अन्य एक्सप्रेस वे, जिनमें बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे शामिल हैं, इन पर कार्य चल रहा है।

अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। प्रदेश में फिल्म सिटी का विकास पीपीपी मोड पर किया जा रहा है। यह उत्कृष्ट और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश की नंबर वन इकोनॉमी बनाने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले छठवें स्थान पर थी आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। निवेश का बेहतर वातावरण वर्तमान सरकार ने तैयार किया है। पहले उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश में चौदहवें स्थान पर था। आज सरकार की नीतियों से दूसरे स्थान पर आ गया है। पांच वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का केन्द्र की किसी योजना में स्थान नहीं होता था। आज केन्द्र सरकार की पैंतालीस योजनाओं में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में दो करोड़ इकसठ लाख शौचालय बनवाये गये हैं। इसी तरह उज्ज्वला, सौभाग्य,उजाला,पीएम किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर कार्य किया है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे और डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए लाभप्रद है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बुंदेलखंड तथा विन्ध्य क्षेत्र में हर घर नल योजना प्रारंभ की गयी है। पहले सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन दयनीय होता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार वर्षों में उत्तर प्रदेश के ओवर ऑल परसेप्शन को बदल दिया है। प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफॉर्म करके, परफॉर्म करते हुए ट्रांसफॉर्म किया है। मश्दा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाएं प्रदेश में लागू हुईं। जिससे किसानों को कृषि कार्य में काफी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश में बीस नये कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गयी है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अन्तर्गत दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया है। ग्यारह लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया। जिनसे करीब सवा दो लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सश्जन हुआ है। तीन सौ इकतालीस किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण महत्वपूर्ण अवसर है। कुछ समय बाद दो सौ सत्तानबे किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण होगा। पांच सौ चौरानवे किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस–वे का निर्माण औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। इक्यानवे किमी लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का काम जारी है। इसी प्रकार बलिया लिंक एक्सप्रेस–वे भी बन रहा है।

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके अंतर्गत चौदह हजार किमी से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया है। तीन लाख पचास हजार किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है। एक सौ चौबीस लंबे ब्रिज,चौवन रेल फ्लाइओवर के काम पूरे हुए हैं। दस महानगर जिनमें नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजना पर काम चल रहा है।

जाहिर है कि व्यापक प्रयासों से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार का संकल्प लिया था। इसके अनुरूप प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। संयोग यह है कि उन्हीं के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। यहां विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे। लाजिस्टिक सुविधा बेहतर होने से स्थानीय कारोबारियों, छोटे व्यापारियों आदि को भी लाभ होगा। पूर्वांचल के छोटे–छोटे जिलों से अब लखनऊ और दिल्ली की दूरी घट गई है। दस घंटे का सफर महज साढ़े तीन से चार घंटे में तय किया जा सकेगा। इस पूर्वांचल एकसप्रेस वे का लाभ बिहार के सीमावर्ती जिलों को भी सीधे मिल सकेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पुरुष प्रधान समाज की वीभत्स कल्पना है भूतनी या चुड़ैल

–निर्मल रानी–

पिछले दिनों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने देश की अनेक हस्तियों को देश के सबसे बड़े एवं प्रमुख पदम् पुरस्कारों से नवाजा। इनमें सरकार द्वारा संस्तुति प्राप्त जहाँ कंगना रानावत जैसे कई नाम ऐसे थे जिन्हें सरकार ने श्अपना समझकर श पदम् पुरस्कार दिलवाये वहीं निश्चित रूप से कई ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज की मुख्य धारा में पसरी कुरीतियों के विरुद्ध अपनी अकेली परन्तु सशक्त आवाज बुलंद की। ऐसा ही एक नाम था झारखण्ड राज्य के सरायकेला जिले की रहने वाली छुटनी देवी का जिन्हें राष्ट्रपति महोदय ने पदमश्री पुरस्कार से नवाजा।

गौर तलब है कि हमारे देश में केवल दिखावे के लिये या महिलाओं के वोट बैंक पर कब्जा जमाने की गरज से महिलाओं को खुश करने के लिये तरह तरह की बातें सत्ता,सरकार,राजनेताओं व प्रशासन द्वारा की जाती है। कभी देवी तो कभी आधी आबादी कहकर खुश किया जाता है। हद तो यह है कि जहाँ महिलायें महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ती हैं,आम तौर पर वहां भी उन प्रत्याशी महिलाओं के पतियों का ही वर्चस्व रहता है। महिलाओं को तो केवल हस्ताक्षर करने मात्र के लिये ही सीमित रखा जाता है। कन्या पूजन के नाम पर कंजकों को पूजा जाता है परन्तु दुनिया में सबसे अधिक बलात्कार,सामूहिक बलात्कार और मासूम व नाबालिग बच्चियों से बलात्कार व उनकी हत्याओं की घटनायें भी इसी श्भारत महान श में घटित होती हैं। बिहार,झारखण्ड,छत्तीसगढ़,मध्य प्रदेश व ओड़ीसा जैसे राज्य जहां गरीबी और अशिक्षा अधिक है वहां तो महिलाओं को नीचा दिखाने,उनसे किसी बात का बदला लेने,कुछ नहीं तो अनपढ़ पुरुषों द्वारा समाज में अपना दबदबा दिखाने या रुतबा जमाने के लिये किसी भी महिला को डायन अथवा चुड़ैल बता दिया जाता है। कभी कभी तो परिवार के लोग ही महिला का मकान जमीन का हिस्सा हड़पने के लिए भी उसे डायन बता देते हैं। और किसी महिला को एक बार डायन घोषित करने के बाद उसपर चाहे जितना जुल्म समाज ढाये कोई उस गरीब महिला के पक्ष में नहीं खड़ा होता। डायन घोषित की गयी महिला को कभी रस्सियों से तो कभी किसी खूंटे या चारपाई में बाँध दिया जाता है तो कभी किसी पेड़ या खंबे से। उसे मारा पीटा जाता है और भूखा भी रखा जाता है। कई बार तो उसके बच्चों को भी चुड़ैल घोषित महिला के साथ ही तिरस्कृत किया जाता है।

झारखण्ड की छुटनी देवी भी उन्हीं महिलाओं में एक थी जिसे वर्ष 2015 में उसके गांव के कलंकी पुरुषों ने डायन घोषित कर दिया था। उस समय छूटनी देवी का आठ महीने का बच्चा भी था। फिर भी गांव के लोगों को उसपर तरस न आया। बताया जाता है कि छुटनी देवी महतो के घर के साथ वाले किसी कथित स्वयंभू दबंग के घर में कोई बीमार पड़ गया। उन लोगों को शक हुआ कि उसकी पड़ोसन छूटनी देवी ने ही कोई झाड़ फूँक की है जिसके परिणाम स्वरूप ही उनके घर का सदस्य बीमार पड़ा है।बस फिर क्या था ?छूटनी देवी पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के पुरुषों की पंचायत हुई और उसे गांव से बाहर निकालने का श्तालिबानी फरमानश जारी कर दिया गया। वह अपने आठ महीने के बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रहने लगी। फिर ओझा के कहने पर छुटनी को मानव मल मूत्र खिलाने की कोशिश की गयी।उसके मना रने पर उसपर मैला फेंका गया। वह न्याय के लिये दर दर भटकती रही परन्तु कहीं से उसे कोई मदद न मिली। फिर छुटनी देवी ने संकल्प किया कि यह समस्या केवल उसी की नहीं बल्कि रोजाना सैकड़ों महिलाओं के साथ यही जुल्म और अन्याय होता है। और फिर छुटनी महतो ने इस प्रकार की पीड़ित महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। आज छूटनी देवी चड़ैल और भूतनी बताकर पीड़ित की जाने वाली महिलाओं की एक सशक्त आवाज बन चुकी हैं। केवल झारखण्ड ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य की उस पीड़ित महिला की वह एक मुखर आवाज हैं जिसे भूतनी बताकर तिरस्कृत या अपमानित किया जाता है। छुटनी महतो अब तक इस प्रकार की दो सौ से भी अधिक पीड़ित महिलाओं को उनपर लगे श्भूतनीश या श्चुड़ैलश अथवा श्डायनश के टैग से मुक्ति दिला चुकी हैं। आज वे बाकायदा अपना श्डायन पुनर्वास केंद्रश संचालित कर रही हैं।

परन्तु दुःख का विषय है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अभी तक हमारे श्गौरवमयी श देश से इस पाखण्ड पूर्ण कुप्रथा का अंत नहीं हो सका ? पुरुष प्रधान समाज में भूतनी ,चुड़ैल या डायन का कोई पुरुष संस्करण नहीं पाया जाता। यह भी कितने कमाल की बात है। ठीक उसी तरह जैसे पुरुषों ने सभी गलियां, गन्दी से गन्दी गलियां सब केवल महिलाओं की और संकेत करने वाली गढ़ी हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए भूतनी ,चुड़ैल या डायन की संकल्पना पुरुषों की उसी दूषित सोच की उपज है। इस कलंक रुपी समस्या के निवारण के लिये जहाँ उस परिवार के पुरुषों को भी मुखर होने की जरुरत है जिसके परिवार की महिला इसतरह की साजिश का शिकार होती है। वहीं सरकार को भी इस कुप्रथा के विरुद्ध सख्त कानून बनाने और दोषी लोगों तथा मात्र अपनी रोजी रोटी के लिये अन्धविश्वास फैलाने वाले ओझा–तांत्रिक आदि के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये।

हिन्दी बने व्यवहार और ज्ञान की भाषा

–गिरीश्वर मिश्र–

अक्सर भाषा को संचार और अभिव्यक्ति के एक प्रतीकात्मक माध्यम के रूप ग्रहण किया जाता है। यह स्वाभाविक भी है। हम अपने विचार, सुख–दुख के भाव और दृष्टिकोण दूसरों तक मुख्यतः भाषा द्वारा ही पहुंचाते हैं और संवाद संभव होता है।

निश्चय ही यह भाषा की बड़ी भूमिका है परंतु इससे भाषा की शक्ति का केवल आंशिक परिचय ही मिलता है क्योंकि शायद ही कुछ ऐसा अस्तित्व में हो जो भाषा से अनुप्राणित न हो। भाषा से जुड़ कर ही वस्तुओं की अर्थवत्ता का ग्रहण हो पाता है। यही सोच कर भाषा को जगत की सत्ता और उसके अनुभव की सीमा भी कहा जाता है। सचमुच जो कुछ अस्तित्व में है वह समग्रता में भाषा से अनुविद्ध है।

सत्य तो यही है कि भाषा मनुष्य जाति की ऐसी रचना है जो स्वयं मनुष्य को रचती चलती है और अपनी सज्जनात्मक शक्ति से नित्य नई नई संभावनाओं के द्वार खोलती चलती है। हम ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला आदि अर्थात सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत शामिल उन सभी तत्वों का अनुभव जिन पर हम गर्व करते हैं, भाषा के द्वारा ही कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में भाषाई निपुणता मनुष्यता का पर्याय हो जाती है। ऐसे में भाषा अतुलनीय संपदा का रूप ले लेती है और तब यह सापेक्षिक वर्चस्व से जुड़ जाती है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा से संबद्ध होकर स्वयं भाषा का अस्तित्व राज–सत्ता पर आश्रित होने लगता है। सत्ता के समीकरण के साथ भाषाओं का दायरा संकुचित या विस्तृश्त होता रहता है।

यह एक सुखद आश्चर्य है कि भाषा की दृष्टि से भारत विश्व का एक अत्यंत समश्द्ध देश है जहां सहस्राब्दियों से कई भाषाओं का प्रयोग होता आया है। इस क्रम में अवाचिक चरण से होकर लिपि के आविष्कार और उपयोग के साथ कई भाषाओं के प्रचुर साहित्य की उपस्थिति दर्ज हुई है। सिर्फ संस्कृत भाषा को ही लें, जो एक अतिप्राचीन भाषा है, तो भारत की विकसित ज्ञान–परम्परा की विशदता और गहनता का पता सहज में लग सकता है और यह भी मालूम हो सकता है कि इस महान भाषा को किस षड्यंत्र से ज्ञान की औपचारिक या प्रामाणिक व्यवस्था से ही बहिष्कृत कर दिया गया।

चूंकि भाषा में ही संस्कृति बसती है इसलिए संस्कृत को परे ढकेल कर भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की अंग्रेजों की योजना कामयाब हो गई। तब अपनी ही संस्कृति पराई लगने लगी और उसके जीवन–मूल्य संदेह के घेरे में आ गए। दूसरी ओर अंग्रेजी साम्राज्य ने अपने भारतीय उपनिवेश में अपनी प्रभु–सत्ता की विशिष्टता स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा को जिस तरह से भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में स्थापित किया। इसके द्वारा अंग्रेजों ने सोच–विचार और व्यवहार को इस तरह अंग्रेजीमय बना दिया कि अंग्रेजी ही प्रामाणिक हो गई और शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उसका दबदबा स्थापित होता गया। दूसरी ओर भारतीय भाषाओं के साथ एक किस्म की हीनता की भावना जुड़ गई। चूंकि भाषा का आत्म–गौरव और अस्मिता के साथ गहरा संबंध होता है इसलिए इसका व्यापक असर देश के साथ जुड़ाव पर भी पड़ता रहा।

अंग्रेजी भाषा के अभूतपूर्व प्रभुत्व ने भारतीय मानस में एक मूल्य और आदर्श का स्थान ले लिया। हमने यह नहीं देखा कि जर्मन, फ्रांसीसी, स्पैनी, चीनी, रूसी, जापानी, कोरियाई और हिब्रू आदि भाषाओं में पढ–लिखकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करने की क्षमता विकसित होती है। इन सब देशों में विश्व स्तर के विश्वविद्यालय भी स्थापित हैं। हम लोगों के नेताओं के मन में यह भाव घर कर गया कि अंग्रेजी ही दुनिया के लिए, ज्ञान और प्रगति के लिए इकलौती राह है। हमने अंग्रेजी वाली विचार–दृष्टि को एक सार्वभौमिक सत्य मान लिया और उसी का गुणानुवाद करने में जुटे रहे। इस दुराग्रह के प्रभाव में अंग्रेजी भाषा भारतीय समाज को जड़ों से काटने, उसे मौलिक चिंतन से महरूम करने और पर निर्भर बने रहने के लिए अभिशप्त करती रही. हम निरुपाय हो गए और अंग्रेजी की जकड़ इतनी मजबूत होती गई कि स्वतंत्र होने के सत्तर साल बीतने के बाद भी आज देश में भाषाई और स्वराज का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। फलतः मन और बुद्धि बंधक हो चली है और विचारों में भी स्वराज नहीं आ सका।

यह ध्यातव्य है कि ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में भी हम वहां नहीं पहुंच सके जो अभीष्ट था और जहां पहुंचना चाहिए था। आज भी कोई विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा का संस्थान विकसित नहीं हो सका है और हमारी ज्ञान–दृष्टि अधिकांशतः यूरोप और अमेरिका की छाया मात्र ही बन सकी। हमारे मेधावी छात्र अध्यापक उन्हीं को संदर्भ बिंदु मानते हैं। इस पश्ठभूमि में हम भारत को भारत की दृष्टि से देखने का कोई अभ्यास ही विकसित नहीं कर सके और उसकी उपादेयता के बारे में भी संशय बना रहा। अब जब वैश्वीकरण का दौर चला तो फिर ज्ञान और ज्ञान की पद्धति का पश्चिम से आयात कुछ और तीव्र हो गया। हम विशेषज्ञता के लिए पश्चिम की ओर मुंह किए रहते हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच ज्ञान–विज्ञान का विनिमय पर यह सारा उपक्रम एकतरफा होकर रह गया। अल्पकालिक दृष्टि से इस युक्ति के कुछ लाभ हो सकते हैं परंतु दूरगामी दृष्टि से इसके नुकसान ही हैं।

सामाजिक दृष्टि से देखें तो भाषा के उपयोग को लेकर भारत एक बहुभाषी समाज के रूप में उपस्थित होता है और अनेक भारतीय भाषाएं साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त समश्द्ध हैं। सामान्य जीवन के अनौपचारिक क्षेत्रों (यथा–बाजार, मनोरंजन, घर परिवार) में भाषाई विविधता दिखती है। जनसंचार माध्यमों में भी इसका संज्ञान लिया जा रहा है परंतु ज्ञान निर्माण और प्रशासन में अंग्रेजी ही हावी है।

देश में भाषा को लेकर संजीदगी से विचार नहीं हो पा रहा है। अभी तक कोई भाषाई नीति नहीं बन सकी है और इसके कई दुष्परिणाम हो रहे हैं। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के बाहुल्य और प्रबल्य के चलते, जो केवल दस–बारह प्रतिशत भारतीयों की समझ में आती है, अधिकांश जन–जीवन में क्षोभ और कठिनाई का अनुभव होता है। इससे अनपेक्षित रूप से कार्य–हानि, विभिन्न अवसरों पर भेद–भाव और गैर–अंग्रेजीदां भारतीयों की मानवीय गरिमा को हानि पहुंचती है। फलतः मानवाधिकार के हनन की सी स्थिति बनती है।

शिक्षा के माध्यम के रूप में मातश्भाषा का उपयोग सर्वत्र स्वीकृत है तथापि अंग्रेजी को थोपने का प्रयास चालू है। यह बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों के लिए हानिकारक है। इस तथ्य की सतत अनदेखी की जाती रही है और अभी भी कोई स्पष्ट नीति उपयोग में नहीं आ रही है। विद्यालयों में भाषा–अध्ययन के स्वरूप को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया ताकि पूरे देश में विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार हो। परंतु यह कार्य अभी तक समुचित रूप से नहीं हो सका है।

भारतीय संविधान ने निर्विवाद रूप से हिंदी को राज भाषा के रूप में स्वीकार किया और अंग्रेजी के उपयोग को तब तक सशर्त अनुमति दी जब तक हिंदी के प्रयोग की तैयारी पूरी न हो जाय। यह विचार समस्त देश के लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया। व्यावहारिक स्तर पर इस कार्य के लिए कई उपाय भी शुरू हुए। राज–भाषा विभाग की स्थापना के साथ ही, शब्दकोश तथा पुस्तक आदि सामग्री का निर्माण, भाषा तकनीकी का विकास, भाषा–प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन आदि के प्रयास होते रहे परंतु राजनीतिक दांवपेंच और सरकारी कार्य शैली की शिथिलता के फलस्वरूप हिंदी की उपयुक्तता / पात्रता की तिथि निरंतर टलती ही गई और अब वह राजनेताओं की मर्जी पर टिकी हुई है। उपेक्षा के कारण भाषा के प्रति दृष्टिकोण में गंभीरता नहीं आ सकी और हिंदी को लेकर दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा / मास की उत्सवधर्मिता से आगे बढ़कर स्थायी कार्य नहीं हो सका। ऐसे ही विभिन्न सरकारी संस्थान पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सके हैं।

उल्लेखनीय है कि किसी भी देश की उपलब्धि केवल आर्थिक पैमानों पर नहीं आंकी जा सकती। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भाषा के रूप में प्राप्त विरासत को संभालने और उसे संवर्धित करते हुए स्वयं को सम्पन्न बनाने की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा सका। इसका परिणाम नई पीढ़ी में भाषा और संस्कृति के संस्कारों के दुर्बल होने में दिख रही है। यह स्थिति सुधी जनों तथा समाज के हितैषियों के लिए समान रूप से चिंतनीय है। इस तरह के सरोकारों पर चिंतन और उपयोगी हस्तक्षेप के लिए गैर सरकारी संगठनों की विशेष भूमिका है। आज आवश्यक है कि लोकभाषा हिंदी ज्ञान की भाषा बने और हम उसके उपयोग में गौरव का बोध करें। राजभाषा की प्रतीकात्मक सत्ता को जन व्यवहार में स्थापित करना ही एकमात्र विकल्प है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

गुमशुदा व्यापारी पुत्र को 12 घण्टे के अन्दर पुलिस ने किया बरामद शत- प्रतिशत रुपये भी बरामद, परिजनो ने पुलिस को दिया धन्यवाद

अवध की आवाज ब्यूरो

कहोबा चौराहा गोंडा। दिनाक 15.11.2021 को व्यापारी विशाल कुमार जयसवाल पुत्र स्व0 केशरी प्रसाद जयसवाल नि0 मालवीय नगर चौक थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ने थाना आकर सूचना दिया था कि उनका छोटा पुत्र सक्षम जयसवाल उम्र 20 वर्ष सुबह 11.30 बजे कैश जमा करने स्कूटी से बैंक के लिए निकला था वापस घर नही आया जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में गुमशुदगी दर्ज की गयी थी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेकर थाना को0नगर व सर्विलांस सहित पाँच टीमें गठित कर गुमशुदा व्यापारी पुत्र की शीघ्र बरामदगी के निर्देश दिये थे । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर व सर्विलांस की गठित टीमें जनपद गोण्डा सहित आस–पास के जनपदो व गाँवों में गुमशुदा व्यापारी पुत्र की शीघ्र बरामदगी हेतु रवाना हुई थी । सभी टीमो द्वारा अपने तकनीकी माध्यमों से व लोगों से पूछताछ व गोपनीय जानकारी करते हुए लगातार 12 घण्टें तक गहन सुरागरसी –पतारसी करते हुए 12 घण्टें में ही गुमशुदा व्यापारी पुत्र के बारे में सम्पूर्ण जानकारी कर गुमशुदा को शत–

प्रतिशत कैश व स्कूटी के साथ बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान गुमशुदा व्यापारी पुत्र ने अपने व्यक्तिगत कारणों से घर से जाने की बात बताया। गुमशुदा को शत– प्रतिशत कैश व स्कूटी के साथ परिजनों को सुपुर्द किया गया। 12 घण्टें के अन्दर ही सकुशल गुमशुदा व्यापारी पुत्र की बरामदगी हो जाने पर परिजनों नें आभार व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा व पुलिस की गठित समस्त टीमों को धन्यवाद दिया गया। व्यापारी पुत्र उनकी सकुशल बरामदगी होने पर जनपद गोण्डा के समस्त व्यापारियों ने भी पुलिस के इस सराहनीय कार्य की भूरिं भूरिं प्रशंसा की है।

'गुमशुदा व्यापारी पुत्र को 12 घण्टे के अन्दर ही सकुशल बरामद कर लिये जाने पर उत्साह वर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा बरामद करने वाली टीम को 15000/– रूपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर आज होगी अखिलेश की समाजवादी विजय रथ यात्रा

लखनऊ,(वेब वार्ता)। समाजवादी पार्टी (सपा) ने बुधवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर आज गाजीपुर से लखनऊ तक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय रथ यात्रा चलाने की घोषणा की है। सपा की ओर से बुधवार को जारी बयान के अनुसार पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक पूरे रास्ते इस यात्रा में साथ चलेंगे। उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। सपा ने इस एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर में अखिलेश का रोड शो एवं रैली करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन गाजीपुर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति देने से इंकार कर दिया था। एक्सप्रेस वे से जुड़े सभी नौ जिलों के सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के आह्वान पर नवनिर्मित एक्सप्रेस वे पर पुष्पवर्षा कर इसका मंगलवार को सांकेतिक उद्घाटन किया। अखिलेश का आरोप है कि केन्द्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सपा सरकार के कार्यकाल में शुरु किये गये कामों का नाम बदलकर उद्घाटन कर रही है। पार्टी की ओर से बताया गया कि अखिलेश के नेतृत्व में विजय रथ यात्रा गाजीपुर से शुरु होकर मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी होते हुये लखनऊ पहुंचेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर विजय रथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले सुबह 11 बजे गाजीपुर में मोहम्मदाबाद के पखनपुर में अखिलेश जनसभा को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे योगी

झांसी, (वेब वार्ता)। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर झांसी में रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू हो रहे तीन दिवसीय झांसी जलसा कार्यक्रम की तैयारियों को जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को झांसी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 17 से 19 नवंबर तक होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ,रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और स्वयं मुख्यमंत्री ने शिरकत करनी है लेकिन उससे पहले तैयारियों की स्थलीय निरीक्षण करने श्री योगी बुधवार को दोपहर वीरांगना नगरी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री एक बजकर 15 मिनट पर यहां डिफेंस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और कार से सीधा कार्यक्रम आयोजन स्थल किले पर पहुंचेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। वह यहां तकरीबन 25 मिनट तक बारीकी से तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद दो बजे सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे । कुछ विश्राम के बाद ढाई बजे मंडलायुक्त कार्यालय में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम और व्यवस्थाओ को लेकर समीक्षा करेंगे। एक घंटे की बैठक के बाद तीन चालीस पर लखनऊ के लिए रवाना हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या सुनीता बंसल ने बुधवार को तहसील सदर के सभागार में महिला उत्पीड़न के मामलों की जनसुनवाई की

सीतापुर। (सू0वि0) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या सुनीता बंसल ने बुधवार को तहसील सदर के सभागार में महिला उत्पीड़न के मामलों की जनसुनवाई की। उन्होंने पीड़ित

महिलाओं को एक एक करके सुना और समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। महिला जनसुनवाई के दौरान कुल 16 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से मौके पर 03 का निस्तारण कर दिया गया।

जनसुनवाई करते हुए श्रीमती बंसल ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करके महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को कम किया जा सकता है। इसके लिये उन्होंने जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश जिला प्रोबेशन अधिकारी को दिये। उन्होंने एक–एक करके महिलाओं से उनका परिचय लिया और उन पर हो रहे शोषण के प्रति अधिकारों से परिचय कराया। उन्होंने घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा का दंश झेल रही महिलाओं को अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु शिकायत कहां करनी व शिकायत करने की प्रक्रिया के विषय में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के लिये चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। परियोजना निदेशक डूडा के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पूर्ण जानकारी दी गयी। उन्होंने लाभार्थियों को जागरूक करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे खाते में आता है, किसी भी बिचौलियों को किसी भी तरह का सुविधा शुल्क देने की जरूरत नही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो यह गलत है उस पर कार्यवाही की जायेगी। समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने शादी अनुदान के लिये आये लाभार्थियों को लगने वाले सभी दस्तावेजों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने ए0सी0एम0ओ0 डा0 आर0एस0 रविदास को निर्देश दिये कि जो गर्भवती महिलाएं अपनी जांच, अल्ट्रासाउण्ड एवं अन्य जाचों हेतु अस्पताल आती हैं उनकी जांच अस्पताल में की जायें। उन्होंने कहा कि यदि जांच सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध नही हैं तो ऐसी स्थिति में निजी पैथालोजी केन्द्रों में उनकी जांच करायी जाये एवं जांच के शुल्क का भुगतान अस्पताल द्वारा कराया जाये।

उन्होंने महिलाओं एवं बालिकाओं से भी अपील की कि वह स्वयं भी

जागरूक हों एवं अन्य को भी जागरूक करें तथा उत्पीड़न की घटनाओं में चुप न रहें और तत्काल महिला हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर अथवा पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है। इससे पूर्व लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में मा0 सदस्या श्रीमती सुनीता बंसल ने पत्रकार बन्धुओं से प्रेसवार्ता कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाया जायेगा। पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाएं समय से उपलब्ध करायी जायेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 मधु गैरोला को निर्देश दिया कि पत्रकारों का यदि कोई फोन आता है तो उनसे वार्ता कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान उपजिलाधिकारी सदर अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर पियूष सिंह, परियोजना निदेशक डूडा सुधीर गिरि, जिला प्राबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, नायब तहसीलदार सदर सुखबीर सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मोहल्ला मिश्राना में शिविर लगाकर हुआ टीकाकरण

अवध की आवाज ब्यूरो

कानपुर। मोहल्ला मिश्राना दक्षिणी वार्ड नम्बर12 के सभासद मनोज मिश्रा के आवास पर कोविड 19 वैक्सीनशन शिविर का आयोजन नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम के रामकिशोर व अनुज ने शिविर में आए लोगों का टीकाकरण किया सभासद मनोज मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा की करोना को हराने के लिए टीकाकरण अति आवश्यक है सभी लोग जागरूक होकर टीकाकरण कराएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस मौके पर आंगन बाड़ी कार्यकत्री राजकिशोरी के अलावा पालिका कर्मी अश्वनी बाजपेई गुलशन जोशी आदि मौजूद रहे।

छेड़खानी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी महोदय बागंरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों की रोकथाम एवं संबन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा छेड़खानी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अखिलेश को बड़ा झटका, सपा के चार एमएलसी ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता

लखनऊ। सपा के चार एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू, नरेन्द्र भाटी, सीपी चंद और रमा निरंजन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। स्वतंत्रत देव सिंह ने कहा कि राज्य में सपा के वफादार सिपाही रहे नरेन्द्र भाटी के जुड़ने से भाजपा को ताकत मिलेगी और सपा का 100 प्रतिशत सफाया होगा।

मौर्य बोले– आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी

रविशंकर सिंह के आने से सपा को बलिया में झटका लगेगा। सीपी चंद के आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। रमा निरंजन के आने से बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। भाजपा में शामिल हुए सदस्य सपा से चुन–चुन कर लोगों को भाजपा से जोड़ने की चिंता करेंगे। अखिलेश जैसे कोरोना के समय आराम कर रहे थे, वैसे ही अभी भी आराम करें। जनता की सेवा करने आए हैं तो मेहनत करनी होगी।

ज्वाइनिंग कमेटी ने दी थी 10 एमएलसी को शामिल करने की मंजूरी

पार्टी सूत्रों के मुताबिक ज्वाइनिंग कमेटी के समक्ष सपा और बसपा के विधायक और एमएलसी सहित 100 बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कराने का प्रस्ताव रखा गया था। समिति ने सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह, रमा निरंजन व बसपा के ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू सहित 10 एमएलसी के भाजपा में शामिल करने की मंजूरी दी।

भाजपा को मिलेगा फायदा, सपा को झटका

सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले परिषद सदस्यों में अधिकांश सदस्य नगर निकाय क्षेत्र से एमएलसी हैं। भाजपा ने इन सदस्यों को विधान परिषद के आगामी नगर निकाय क्षेत्र चुनाव में उम्मीदवार बनाने की भी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सपा के सदस्यों को भाजपा में शामिल कराने में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की बड़ी भूमिका रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इन सदस्यों के भाजपा में शामिल होने से सपा को बड़ा झटका लगेगा। वहीं, भाजपा को इन सदस्यों के प्रभाव वाले क्षेत्र में फायदा होगा।

विधायकों को भी शामिल कराने की तैयारी

भाजपा ने सपा के कुछ मौजूदा विधायकों को भी भाजपा में शामिल कराने की तैयारी की है। इसी महीने में कुछ अन्य एमएलसी और विधायक भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।

गृह प्रवेश पार्टी के बाद पति ने पत्नी को गला दबाकर मार डाला और खुद भी फांसी पर लटका

लखनऊ। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित गंगोत्री विहार फेस दो में नवनिर्मित घर में मंगलवार रात गृह प्रवेश की पार्टी के बाद बुधवार सुबह दंपती का शव संदिग्ध हालात में बेडरूम में मिला। रिश्तेदारों ने खिड़की

का शीशा तोड़ किसी तरह से दरवाजा खोलने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन कर प्रथम दृष्टया पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद पति द्वारा खुदकुशी करने की बात कही है।

मूल रूप से गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के शिवशंकर पुरवा निवासी रंगनाथ मिश्रा के पुत्र रामकिशोर, श्याम किशोर और बृज किशोर गोमती नगर विस्तार में गीतापुरी के पास रहकर बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करते हैं। तीनों भाइयों ने हाल ही में गोमती नगर के गंगोत्री विहार फेस टू में चारमंजिला आलीशान मकान बनवाया है। जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोली गई और ऊपर की दो मंजिलों पर परिवार के लिए आवास बनवाया गया। मंगलवार को नवनिर्मित मकान में गृह प्रवेश की पार्टी थी।

इसमें तमाम रिश्तेदार, मित्र और आसपास के लोग शामिल हुए। देर रात तक खाना पीना और डांस के बाद परिजन व रिश्तेदार सो गए। बुधवार सुबह श्याम किशोर देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो उनकी बहन ने दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर अनहोनी की आशंका में रिश्तेदारों ने कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ा तो भीतर श्याम किशोर (38) का शव फंदे पर लटका देख घबरा गए। दरवाजा तोड़कर रिश्तेदार और परिवार के लोग भीतर गए तो बेड पर साधना (36) की लाश पड़ी थी जबकि श्याम किशोर की 9 साल की बेटी प्रियांशी पास में बैठी थी और 7 साल का बेटा अविनाश सो रहा था। श्याम किशोर और साधना की मौत से परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। आनन–फानन पुलिस को सूचना दी गई। इस पर डीसीपी पूर्वी अमित कुमार आनंद, एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी और गोमती नगर विस्तार इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौका मुआयना करने के साथ ही परिजनों व रिश्तेदारों से पूछताछ की। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। इंस्पेक्टर ने बताया कि फोरेंसिक टीम के साथ मौके का मुआयना कर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

साधना के मायके वालों का कहना है कि श्याम किशोर ने साधना की हत्या कर दी। उसके बाद फंसने के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके वालों का कहना है कि साधना नए घर में जाने को लेकर खुश थी। उसका आत्महत्या करना संभव ही नहीं। दूसरी तरफ श्याम किशोर के परिजनों का कहना है कि दोनों के कमरे का दरवाजा सुबह देर तक न खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने दोनों के बीच देर रात किसी बात को लेकर विवाद की बात स्वीकार की है लेकिन विवाद किस बात पर हुआ इसकी जानकारी होने से इंकार किया।

उप्र में विवादित जमीन खाली कराने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां, कई लोग घायल

मुजफ्फनगर (उप्र) (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के उमेरपुर गांव में भूमि पर कथित तौर पर कब्जा करने वाले लोगों को हटाने के लिए पुलिस के लाठियां भांजने पर छह महिलाओं सहित 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना बुढ़ाना थाना क्षेत्र में मंलगवार को हुई, जब पुलिस ने जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने वाले कुछ लोगों को हटाने के लिए कथित तौर पर लाठियां चला दी। विवादित जमीन लगभग 20 साल पहले यूसुफ नाम के एक व्यक्ति ने खरीदी थी, लेकिन तहसील के रिकॉर्ड में उसका पंजीकरण नहीं कराया था।

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा मे किया सैनिक सम्मेलनध्अपराध गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्दे अवध की आवाज, ब्यूरो चीफ गोंडा, विनोद कुमार सिंह

सामंथा ने पुष्पा में आइटम सॉन्ग के लिए ली मोटी रकम

हैदराबाद, (वेब वार्ता)। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म पुष्पा को कास्ट और क्रू के मामले में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अब सामंथा रुथ प्रभु फिल्म में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

पुष्पा के निर्माताओं ने सोमवार को घोषणा की कि सामंथा रूथ प्रभु को उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पाः द राइज में एक विशेष प्रदर्शन के लिए

चुना गया है। निर्माताओं ने यह भी कहा कि एक स्पेशल गाने में सामंथा की पहली मौजूदगी होगी, जो उनके लिए चीजों को एक साथ रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

इस खबर को साझा करते हुए, फिल्म को बनाने वाले प्रोडक्शन बैनर, मैत्री मूवी मेकर्स ने सामंथा की विशेषता वाला एक पोस्टर साझा किया और अभिनेता का आभार व्यक्त किया।

पुष्पा का 5वां गाना खास है और हमें किसी खास की जरूरत थी! हम अपने बेहद खास सामंथा गारू के पास पहुंचे और वह समय के साथ हमारे द्वारा बनाए गए तालमेल के कारण खुशी से बोर्ड पर आने के लिए तैयार हो गईं। हम सामंथा गारु की घोषणा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। पांचवें गाने में आइकन स्टार अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन पर धमाल मचाने जा रही हैं। यह उनके करियर का पहला स्पेशल गाना होगा और हम इसे वास्तव में यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

जब से घोषणा की गई थी, आगामी क्राइम थ्रिलर पुष्पा में खास गाने के लिए सामंथा के पारिश्रमिक पर अटकलें लगाई जा रही हैं। जबकि कुछ मीडिया घरानों की रिपोर्ट है कि माजिली की अभिनेत्री ने 1.5 करोड़ तक की भारी कीमत की मांग की है, इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सुकुमार द्वारा अभिनीत, पुष्पा में लोकप्रिय मलयालम अभिनेता फहद फासिल भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अभिनेता सुनील, अभिनेत्री अनसूया भारद्वाज, और अन्य को भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देना है। मल्टी–स्टारर, बहुभाषी फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित पांच भाषाओं में रिलीज होगी।

यशराज फिल्म्स अपने पहले ओटीटी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी

मुंबई, (वेब वार्ता)। प्रोडक्शन पावर हाउस यश राज फिल्म्स के मुखिया आदित्य चोपड़ा चार हीरो

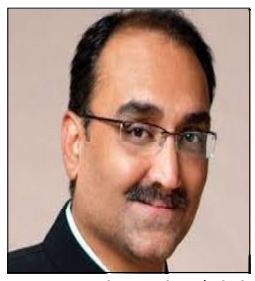

स्टारर अपनी पहली ओटीटी परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि यशराज अपनी परियोजना के लिए 100 करोड़ खर्च करके अपने डिजिटल प्रोजेक्ट से अच्छी सामग्री का उत्पादन करना चाहते हैं। वे भारत में सामग्री के लिए एक आदर्श बदलाव करना चाहते हैं और यह पहली परियोजना अव्यवस्था तोड़ने वाली परियोजनाएं बनाने के उनके विश्वास का प्रमाण होगी। सूत्र ने आगे कहा कि यशराज ओटीटी पर बहुत बड़ी और धमाकेदार शुरुआत करना चाहते हैं। सूत्र ने साझा किया कि यशराज इस परियोजना को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि यह देश में चर्चा का विषय बन जाए। 12 नवंबर को, यह घोषणा की गई थी कि फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा की डिजिटल सामग्री बाजार को फिर से आकार देने की भव्य योजना बना रही है।

मानुषी छिल्लर की हिंदी सिनेमा में उड़ान देखने के लिए उत्साहित हैं अक्षय कुमार

मुंबई, (वेब वार्ता)। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपनी को–एक्टर मानुषी छिल्लर की जमकर तारीफ की है। वह यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि मानुषी हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी छाप कैसे छोड़ती हैं। अक्षय ने कहा कि मानुषी की निस्संदेह देखने लायक प्रतिभा है। पश्थ्वीराज पहली फिल्म होने के बावजूद, वह इतनी सहज, इतनी जिज्ञासु और इतनी समर्पित थी कि उन्होंने पूरी टीम का दिल जीत लिया है। मानुषी ने फिल्म में राजकुमारी संयोगिता की भूमिका निभाई है। अक्षय ने आगे कहा कि हमारे निर्देशक डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने सही संयोगिता पाई है क्योंकि मानुषी अपनी कृपा और अपने माता–पिता द्वारा दिए गए जीवन मूल्यों के माध्यम से भारतीय महिलाओं की भावना का प्रतीक हैं, जो अंदर से सुंदर हैं। मैं यह देखने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं कि मानुषी कैसे हमारे हिंदी फिल्म उद्योग में एक पहचान बनाती हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी खुले हाथों से उनका स्वागत करेंगे। मुझे राजकुमारी संयोगिता के रूप में उनका परिचय देते हुए वास्तव में गर्व हो रहा है। पश्थ्वीराज सम्राट पश्थ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता पर आधारित है। अक्षय इस फिल्म में योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने बेरहम आक्रमणकारी मौहम्मद गौरी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित पश्थ्वीराज का निर्देशन डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है। यह 21 जनवरी 2022 को दुनियाभर में रिलीज होगी।

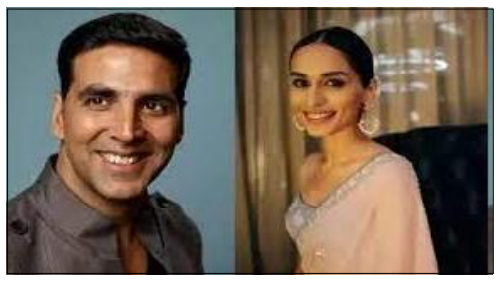

पेट्रोल–डीजल के दाम 13वें दिन भी स्थिर

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी नरमी के बीच घरेलू स्तर पर सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार तेरहवें दिन भी स्थिर रहे। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः पांच रुपये तथा 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करने से देश में इसकी कीमतों में कमी आयी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन दोनों उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी की है। इससे संबंधित राज्यों में इन दोनों पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में और कमी आयी है। इसका असर आज भी पेट्रोल–डीजल की कीमतों पर बरकरार है। इस बीच राजस्थान ने भी पेट्रोल–डीजल पर वैट में कटौती कर दी है। राज्य में पेट्रोल की कीमत में चार रुपये प्रति लीटर और डीजल में पांच रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। इस कटौती के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 107.06 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है। घरेलू बाजार में बुधवार को 13वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पंप पर पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर पर टिके रहे। पेट्रोल–डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नई कीमतें लागू की जाती हैं।

देश को असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं, सबके प्रयास से ही यह संभव होगा : मोदी

शिमला, वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तथा असाधारण लक्ष्यों का हासिल करना है और यह संकल्प ''सबके प्रयास'' से ही पूरा होगा।

प्रधानमंत्री ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम् मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कांफ्रेंस के माध् यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था में जब ''सबका प्रयास'' की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। उन्होंने कहा, ''हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है व असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प 'सबके प्रयास' से ही पूरे होंगे।''

उन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में राज्यों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि ''सबके प्रयास'' के बगैर इस लड़ाई के खिलाफ जीत हासिल करना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि आज भारत कोविड–19 रोधी टीकों की 110 करोड़ खुराक अपने देशवासियों को दे चुका है।

मोदी ने कहा, ''जो कभी असंभव लगता था, वह आज संभव हो रहा है। इसलिए हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, संकल्प हैं, वह भी पूरे होंगे। यह, देश और राज्यों के एकजुट प्रयासों से ही पूरे होने वाले हैं।'' उन्होंने कहा कि यह समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है, और जो रह गया है उसे पूरा करने का है।

उन्होंने कहा, ''एक नई सोच और नई दृष्टि के साथ हमें भविष्य के लिए नई नीतियां और नियम भी बनाने हैं। सदन की परम्पराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हों, हमारी नीतियां, हमारे कानूनों में भारतीयता के भाव को, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को मजबूत करने वाली हों, तथा सबसे महत्वपूर्ण बातढ ढकृकृ , सदन में हमारा खुद का भी आचार–व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम् मेलन के 82वें संस् करण का आयोजन 17–18 नवम् बर, 2021 को शिमला में किया जा रहा है। प्रथम सम् मेलन का आयोजन भी शिमला में 1921 में किया गया था। इस अवसर पर लोकसभा अध् यक्ष ओम बिरला, राज् यसभा के उपसभापति हरिवंश, हिमाचल प्रदेश के मुख् यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में राज्यों की विधानसभाओं के सभापति, पीठासीन अधिकारी शामिल हुए और इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को पारदर्शी एवं मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की जानी है।

सलमान खान उठाएंगे मुस्लिमों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का जिम्मा, महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

मुंबई, (वेब वार्ता)। पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इस वायरस से बचाव के लिए कई

वैक्सीन आ चुकी हैं लेकिन अभी तक भारत में काफी लोगों ने यह वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है। अब महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करने में बॉलिवुड सुपरस्टार सलमान खान की मदद लेने का फैसला किया है। सलमान खान लोगों को कोविड वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करेंगे।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कई मुस्लिम इलाकों में लोग कोरोना वायरस की रोकथाम वाली वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। लोगों में इस वैक्सीन को लेकर तरह–तरह के वहम हैं। इसलिए सलमान खान अब लोगों को वैक्सीन लिए जाने के लिए जागरूक करेंगे।

टोपे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैक्सिनेशन के मामले में महाराष्ट्र काफी आगे है लेकिन कुछ इलाकों में यह काम काफी धीमा हो रहा है। उन्होंने कहा, 'मुस्लिम बहुल इलाकों में वैक्सिनेशन बहुत धीमा है। हमने फैसला किया है कि सलमान खान और धार्मिक गुरु मुस्लिमों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेंगे क्योंकि ऐक्टर्स और धार्मिक गुरुओं से लोग काफी प्रभावित होते हैं।'

महाराष्ट्र में अब तक 10.25 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं और नवंबर के अंत तक 18 साल से ऊपर सभी लोगों को पहली डोज लग चुकी होगी। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में पूछे जाने पर राजेश टोपे ने कहा कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी का साइकल 7 महीने का होता है लेकिन वैक्सीनेशन के कारण अब तीसरी लहर का आना मुश्किल है फिर भी लोगों को सावधानी बरतने और मास्क लगाने की जरूरत है।

टेस्ट मैचों पर ध्यान देने के लिये भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला से हटे जैमीसन

जयपुर, (वेब वार्ता)। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने के लिये तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला से हटने का फैसला किया है। जैमीसन इस तरह के कप्तान केन विलियमसन की श्रेणी में शामिल हो गये हैं जिन्होंने 25

नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला की तैयारी के लिये टी20 मैचों से हटने का फैसला किया था। टेस्ट श्रृंखला नये विश्व टेस्ट चौंपियनशिप चक्र की पहली श्रृंखला होगी। स्टफ.सीओ.एनजेड के अनुसार कोच गैरी स्टीड ने कहा, ''हमने केन और काइल से बातचीत करने के बाद फैसला किया कि वे टी20 श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा, ''वे दोनों टेस्ट मैचों की तैयारी करेंगे और मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि टेस्ट टीम में शामिल कुछ अन्य खिलाड़ी भी पूरी श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। स्टीड ने कहा, ''यह पांच दिन के अंदर तीन टी20 मैचों का आयोजन और तीन विभिन्न शहरों की यात्रा करने के कारण संतुलन स्थापित करने का समय है। यह बहुत व्यस्त समय है। न्यूजीलैंड ने इस साल जुलाई में इंग्लैंड के साउथम्पटन में भारत को आठ विकेट से हराकर पहली विश्व टेस्ट चौंपियनशिप जीती थी।

राजस्थान में ट्रांसफर माफिया को लेकर केंद्रीय भाजपा नेताओं ने बोला गहलोत सरकार पर हमला

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण वाला एक छोटा वीडियो साझा करते हुए भाजपा नेताओं ने राज्य में सक्रिय ट्रांसफर माफिया को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अशोक गहलोत के वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, सत्यम् किम् प्रमाणम, प्रत्यक्षे किम् प्रमाणम्! राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि हां, उन्हें ट्रांसफर्स के लिए घूस खिलानी पड़ती है। जब इतने बड़े स्तर पर राज्य में ट्रांसफर माफिया सक्रिय हैं तो इसकी आधिकारिक जांच होनी ही चाहिए।

राठौड़ ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग करते हुए अगले ट्वीट में कहा, जांच पूर्ण होने तक, शिक्षा मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वे स्वयं पद नहीं छोड़ते तो मुख्यमंत्री को उन्हें पद से हटाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के भाषण वाले वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया, जब भविष्य निर्माता शिक्षक ही स्वीकारने लगें कि उन्हें स्थानांतरण के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और वह भी राज्य शिक्षा मंत्री के सामने तो बच्चा भी समझ सकता है कि राज्य का वर्तमान कैसा है? मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सवाल कर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार पर मुहर लगा दी।

शेखावत ने अगले ट्वीट में लिखा, गहलोत जी के भूतकाल में किए जीरो करप्शन के वादे को सौ पर्सेंट फाल्स कहने में अब उन्हें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षकगण सामूहिक रूप से उनकी तरह झूठ नहीं कह सकते।

राजस्थान के ही बीकानेर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आए।

दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं शिक्षकों से यह सवाल पूछा कि क्या उन्हें ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं? शिक्षकों ने जवाब हां में दिया। शिक्षकों के इस जवाब ने मुख्यमंत्री के साथ–साथ कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री को भी असहज कर दिया और इसी वीडियो का सहारा लेकर भाजपा के दिग्गज नेता गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

राजस्थान सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर वैट घटाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए

जयपुर, (वेब वार्ता)। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर चार रूपए एवं डीजल पर पांच रूपए प्रति लीटर वैट घटाने, कल्याणकारी गतिविधियों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन एवं जनजाति क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का अलग कैडर बनाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में ये फैसले किए गए। बैठक में पेट्रोल एवं डीजल के वैट में कटौती को मंजूरी दी गई जो मंगलवार रात बारह बजे से लागू हो गई। उल्लखेनीय है कि राज्य सरकार ने पहले भी इस वर्ष के प्रारंभ में पेट्रोल–डीजल पर वैट में दो प्रतिशत की कमी कर प्रदेश की जनता को एक हजार करोड़ रूपए की राहत दी थी। इस निर्णय से राजस्व हानि बढ़कर 6300 करोड़ रूपए सालाना हो जाएगी। मंत्रिपरिषद् की बैठक में बताया गया कि पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में लगातार वश्द्धि करने से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आमजन को दी गई राहत में कमी आ रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से पेट्रोल एवं डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार कम किया है और राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले डिविजिएबल पूल के हिस्से को घटा दिया है। इससे राज्यों को मिलने वाले शेयर में कमी आई है, जबकि स्पेशल एवं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाया गया है। राज्यों को इस बढ़ोतरी का कोई हिस्सा नहीं मिलता। मंत्रिपरिषद ने कहा कि केंद्र का यह कदम वित्तीय संघवाद की भावना के विपरीत है। बैठक में बताया गया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान छह मई 2020 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 एवं डीजल पर 13 रूपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इसके बाद इस वर्ष भी पेट्रोल की करीब 27 और डीजल की कीमत करीब 25 रूपए प्रति लीटर बढ़ी है। अब पेट्रोल पर केवल पांच रूपए और डीजल पर 10 रूपए प्रति लीटर कम कर जनता को राहत देने की बात कही जा रही है। केंद्र द्वारा पेट्रोल पर 5 रूपए तथा डीजल पर 10 रूपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में की गई यह कमी नाकाफी है और जनता को इससे स्थाई राहत नहीं मिल सकेगी।

बैठक में बताया गया कि राज्य के कुल कर राजस्व का 22 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पेट्रोल एवं डीजल पर वैट से आता है। कोविड वैश्विक महामारी के कारण चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में अक्टूबर माह तक 20 हजार करोड़ रूपए की भारी कमी आई है। केंद्र द्वारा राज्य को 5,963 करोड़ रूपए के जीएसटी का पुनर्भरण उपलब्ध नहीं कराना भी इसका एक बड़ा कारण है। मंत्रिपरिषद् ने कहा कि महंगे पेट्रोल एवं डीजल से आमजन को वास्तविक राहत देने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार केंद्रीय पूल में आने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं बेसिक एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। यदि केंद्र सरकार द्वारा प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रूपए तथा डीजल पर 15 रूपए प्रति लीटर की कमी की जाती है तो प्रदेश के वैट में भी पेट्रोल पर 3 रूपए 40 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 3 रूपए 90 पैसे स्वतः कम हो जाएंगे। समस्त आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व में होने वाली करीब 3500 करोड़ रूपए की अतिरिक्त हानि को भी वहन करने के लिए तैयार है।

इटली ने सार्वजनिक परिवहन पर कोरोना नियमों को किया सख्त

रोम, (वेब वार्ता)। इटली में सार्वजनिक परिवहन और टैक्सियों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नए उपाय मंगलवार से लागू हो गए हैं। अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण की चौथी लहर को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों के तहत, जिन्हें सोमवार को स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रियों द्वारा जारी एक डिक्री में हस्ताक्षरित किया गया। उसके अनुसार सभी यात्रियों को लंबी दूरी की और अंतर–क्षेत्रीय ट्रेनों में सवार होने से पहले अपना ग्रीन पास दिखाना होगा। ग्रीन पास एक प्रमाण पत्र है जो दर्शाता है कि एक व्यक्ति या तो पूरी तरह से प्रतिरक्षित है या उसने कोरोना वायरस वैक्सीन की कम से कम एक खुराक प्राप्त की है और बीमारी से उबर चुका है या बीते 48 घंटे में निगेटिव परीक्षण किया है। यह नए उपाय रोम, मिलान और फ्लोरेंस सहित देश के सभी प्रमुख ट्रेन स्टेशनों और उन सभी स्टेशनों से संबंधित हैं जहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जांच संभव है। सरकारी फरमान में यह भी कहा गया कि अगर ट्रेन में सवार किसी यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो रेलवे कर्मचारी और पुलिस आपातकालीन हस्तक्षेप के लिए ट्रेन को रोकने का फैसला कर सकते हैं। यह उपाय उन सभी ट्रेनों पर लागू होता है, जिनमें लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं और जिन पर यात्रियों को वर्तमान में ग्रीन पास रखने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइवरों के साथ टैक्सी और कार किराए पर लेने की सेवाएं (एनसीसी) अब अधिकतम दो यात्रियों तक सीमित हैं, सिवाय इसके कि यात्री एक ही परिवार के सदस्य हों। अब तक, कुछ अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में चौथी लहर का इटली में समग्र महामारी की स्थिति पर सीमित प्रभाव पड़ा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार हफ्तों से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इटली के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (आईएसएस) की लेटेस्ट रिपोर्ट में पिछले सप्ताह के 53 मामलों की तुलना में नवंबर 5–11 सप्ताह में प्रति 100,000 निवासियों पर 78 मामले दर्ज किए गए हैं। ये दर्शाता है कि पिछली अवधि में 1.15 की तुलना में 20 अक्टूबर और 2 नवंबर के बीच प्रजनन संख्या (आरटी) 1.21 थी। एक के ऊपर एक प्रजनन संख्या इंगित करती है कि वायरस तेजी से फैल रहा है और इसका मतलब है कि एक संक्रामक व्यक्ति औसतन संक्रमण को एक से अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। इटालियन स्वास्थ्य अधिकारी टीकाकरण अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से लोगों को पहले के 6–9 महीने बाद तीसरी टीका खुराक प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसे नए बड़े प्रकोपों के जोखिम को रोकने के सर्वोत्तम तरीके के रूप में देखा जाता है, जो अब पूरी तरह से प्रतिरक्षित लोगों के उच्च प्रतिशत को देखते हुए (15 नवंबर तक 12 वर्ष से अधिक आयु की लक्षित आबादी का 84.2 प्रतिशत) है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए तीसरी खुराक सितंबर से मिलनी शुरू हुई। साथ ही यह अक्टूबर तक जारी रहा और अब यह 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को लक्षित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाली पहली खुराक से कम से कम छह महीने, 40 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को बूस्टर शॉट्स की पेशकश शुरू हो जाएगी। इटली ने मंगलवार तक कुल 48 लाख कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 132,000 से अधिक घातक और 46 लाख से ज्यादा रिकवर हुए हैं।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।